देहरादून,पौड़ी–गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 109 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार–प्रवाह...पाक पर ज्यादा जोर

पेज श्री

देहरादून, बुधवार, 28 जुलाई 2021

मौसम अधिकतम 26.0^{0} न्यूनतम 24.0^{0}

42243.40

2 अफगान ने भारत को दी चेतावनी

7 क्रुणाल पंड्या को हुआ कोरोना

दो से खुलेंगे छठी से 12वीं तक के स्कूल

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में कोविड–19 के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों में छठी से लेकर 12 वीं तक की कक्षाएं एक अगस्त से शुरू हो जाएंगी । मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड–19 के कारण प्रदेश के शिक्षण संस्थान काफी लंबे समय से बंद पड़े हैं और मंत्रिमंडल ने अब छठी से लेकर 12 वीं तक की कक्षाओं का संचालन एक अगस्त से शुरू करने का निर्णय किया है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ऊधमसिंहनगर जिले के पंतनगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु चयनित भूमि पर निर्माण शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को परामर्शी नियुक्त करने का फैसला लिया गया । उन्होंने बताया कि इसे छह माह के भीतर सरकार को डीपीआर उपलब्ध करानी होगी ।

धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

राज्य लोकसेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर मिलेंगे 50 हजार

प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र 23 से 27 अगस्त तक आयोजित करने पर भी अपनी मुहर लगा दी। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को तैयारी के लिए 50,000 रू देने, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (पीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को तैयारी के लिए 50,000 रू देने एवं एनडीए तथा सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने वालों को भी 50,000 रूपये देने का निर्णय लिया ।

प्रदेश में कई विभागों में वेतन विसंगति संबंधी प्रकरणों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति बनाने को भी मंजूरी दे दी जो अधिकतम तीन माह में अपनी संस्तुति देगी।

एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने बागेश्वर जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौसानी का ग्राम पंचायत से दर्जा बढाते हुए उसे नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी ताकि वहां आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या के अनुरूप अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा सकें ।

चारधाम यात्रा एवं पर्यटन पर आर्थिक राहत पैकेज को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने कोविड–19 के कारण चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत 197.85 करोड़ रू के आर्थिक राहत पैकेज को मंजूरी दे दी जिसके तहत नैनीताल जिले में नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एंव सड़ियाताल में पंजीकृत कुल 549 नौका संचालकों को 10,000 रू की दर से आर्थिक सहायता की जाएगी।

भीमताल, सात ताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट

नैनीताल में नैनीझील में नौका लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में छूट दी जायेगी। इसके अलावा, सांस्कृतिक दलों को पांच माह तक दो हजार रू प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना हेतु ऋण पर छह माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता की जाएगी। उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन निगम के कार्मिकों को तीन माह का वेतन 51.24 करोड रू की धनराशि देने के बारे में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया। मंत्री ने बताया कि कोविड 19 की शुरूआत के बाद से राज्य सरकार अब तक परिवहन निगम को अपने कार्मिकों को वेतन देने के लिए 209.35 करोड़ रू दे चुकी है।

संक्षिप्त समाचार

कई राज्यों में तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। कई दिनों से गर्मी में जी रहे राजधानी के लोगों को मंगलवार सुबह कुछ राहत मिली। आईएमडी बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है।

असम–मिजोरम के बीच खूनी संघर्ष के बाद तनाव

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

दिसपुर (असम)। असम और मिजोरम के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सोमवार को हुए झड़प में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सीमा संघर्ष में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की।

अभी खत्म नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर

देश के 22 जिलों में कोरोना केस बढ़ रहे, सरकार ने चेताया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। देश में कोरोना और टीकाकरण की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कांफ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा. वी. के. पॉल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ क्षेत्र चिंता का विषय बने हुए हैं। वैक्सीनेशन संक्रमण कम जरूर करेगा लेकिन संक्रमण ना हो इसकी गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जो दावा कर सके कि 100 फीसद संक्रमण नहीं होगा। इससे बीमारी की गंभीरता और मौत को रोका जा सकता है।

संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि शुरू के कुछ हफ्तों में कोरोना के मामलों में एक तेज कमी दर्ज की जा रही थी लेकिन पिछले दो–तीन हफ्तों से कोरोना वायरस के मामलों में हो रही गिरावट की दर कम हुई है जो चिंता का विषय है। हम इसे लेकर राज्यों के साथ बात कर रहे हैं। देश में अभी 22 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 4 हफ्ते में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। इसमें केरल के 7 जिले, मणिपुर के 5 जिले, मेघालय के 3 जिले, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले, महाराष्ट्र के 2 जिले, असम का 1 जिला, त्रिपुरा का 1 जिला शामिल है।

डॉ वीके पॉल ने कहा, एएफएमसी में 15 लाख डॉक्टरों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं पर अध्ययन किया गया था, जिन्हें कोविशील्ड दी गई थी। इस अध्ययन में पता चला कि दूसरी लहर के दौरान संक्रमण में 93 फीसद की कमी आई थी और मृत्यु दर में 98 फीसद की कमी दर्ज की गई थी।

लव अग्रवाल ने कहा, वैश्विक नजरिए से देखें तो महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर में मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। हमें सख्ती के साथ वायरस के प्रसार को रोकने पर काम करना होगा।

देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी

देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, कल 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 30 हजार से कम मामले सामने आए हैं। इस दौरान 29,689 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में अब तक कुल 3,14,40,951 पॉजिटिव मामले दर्ज हो चुके हैं।

पेगासस पर सर्वदलीय सम्मेलन बुलाए पीएम

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि प्रधानमंत्री को पेगासस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। इस मामले की जांच भी होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, यह भी सुनिश्चित हो। उधर, ममता बनर्जी बुधवार को 10 जनपथ पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये सौजन्य भेंट है। हमें और वैक्सीन मिले इसके लिए प्रधानमंत्री से बात की। हमारे राज्य को आबादी के हिसाब से दूसरे राज्यों से बहुत कम वैक्सीन मिली है। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री से आबादी के अनुसार राज्य को और कोविड टीके उपलब्ध कराने की अपील भी की है। उधर, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मुलाकात की जानकारी ट्वीट करके दी। मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए पीएमओ ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

उधर, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मुलाकात की जानकारी ट्वीट करके दी। मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए पीएमओ ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

मुलाकात

■ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की

सोनिया से भी मिलेंगी ममता

ममता बनर्जी कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और विपक्षी दलों के कई अन्य नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। ममता बनर्जी बुधवार को दिल्ली में 10 जनपथ पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

सभी अनाथ बच्चों को मिले योजनाओं का लाभ

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कई राज्यों को फटकार भी लगाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर्स फंड के तहत अनाथों के लिए चलाए जाने वाली सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ उन बच्चों को भी मिले जो कोविड–19 के दौरान अपने माता–पिता को खो चुके हैं न कि केवल उन बच्चों को जो महामारी के कारण अनाथ हुए हैं। कोर्ट ने कई राज्यों को फटकार लगाई क्योंकि स्पष्ट आदेश के बावजूद अनाथ बच्चों के बारे में जानकारी नहीं दी गई।

कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वह अनाथ बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए चाइल्ड केयर हेल्पलाइन, पुलिस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत हर विभाग की मदद लें। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। मंगलवार को कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बड़े होने पर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने सवाल किया कि कोरोना काल में अनाथ हुए सभी बच्चों को यह सहायता क्यों नहीं दी जा सकती?